

1977 and there is now no problem of availability of adequate quantities of coal.

### राज्यों में आदिवासी ग्रामों का विद्युतीकरण

4693. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 28 फरवरी, से पूर्व देश के राज्यवार कुल कितने आदिवासी ग्रामों में बिजली लगाई है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में, जहां आदिवासी ग्रामों की संख्या अधिक है, कम आदिवासी ग्रामों में बिजली लगाई गई है और यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार अधिक धनराशि नियत करने का है ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जिसे पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया है, पुष्पराजगढ़, तहसील में बिजली लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो उसे कब लागू किया जाएगा तथा क्या शहडोल जिले के अन्य आदिवासी खण्डों को भी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :

(क) और (ख). ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है । यह स्थानीय स्थितियों पर निर्भर है । अतः

तुलना से समग्र चित्र प्रतिबिम्बित नहीं होगा । मध्य प्रदेश में आदिवासी गांवों के संबंध में उनके अत्यन्त पिछड़ेपन को दृष्टिगत रख कर, बहुत उदार मानदण्ड अपनाए गए हैं । निगम ने कुल 91.38 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की 200 स्कीमें स्वीकृत की हैं । इनके पूरा हो जाने पर 16,167 गांव विद्युतीकरण हो जाएंगे । 30 सितम्बर, 1977 को स्थिति के अनुसार 3720 नए गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं । राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) निगम ने 42.46 लाख रुपए की ऋण सहायता को एक ग्राम विद्युतीकरण स्कीम को दिसम्बर, 1977 में स्वीकृति दी है । इसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश के शहडोल जिले को पुष्पराजगढ़ तहसील के आदिवासी क्षेत्र आते हैं । इस स्कीम में 98 गांवों के विद्युतीकरण की परिकल्पना है । शुरू से 5 वर्षों की अवधि में पूरा किए जाने के लिए इसे सोपानबद्ध किया गया है ।

निगम ने कुल 204.27 लाख रुपए की ऋण सहायता से 3 और ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें इससे पूर्व स्वीकृत की थीं जिनमें शहडोल जिले के 332 गांवों के विद्युतीकरण की परिकल्पना है । इन में से दो स्कीमों में आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र शामिल हैं ।

शहडोल जिले को कोई अन्य ग्राम विद्युतीकरण स्कीम निगम के पास विचाराधीन नहीं पड़ी है ।

## विवरण

जनजाति क्षेत्रों में स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की राज्यवार स्थिति

क्र० सं०	राज्य	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु०)	इसके अन्तर्गत आए गांवों की संख्या	30-9-77 तक विद्युतीकृत गांव
1.	आंध्र प्रदेश .	24	10.15	1278	262
2.	असम . . .	9	5.73	1042	90
3.	बिहार . . .	24	14.14	3277	588
4.	गुजरात .	8	2.94	406	123
5.	हिमाचल प्रदेश . . .	2	0.67	285	94
6.	मध्य प्रदेश . . .	51	19.51	2967	566
7.	महाराष्ट्र . . .	14	6.00	1069	516
8.	मणिपुर . . .	1	0.43	66	--
9.	मेघालय . . .	10	4.56	639	169
10.	नागालैण्ड . . .	4	2.48	163	31
11.	उड़ीसा . . .	31	12.83	3122	793
12.	राजस्थान .	15	8.56	1271	402
13.	त्रिपुरा .	3	1.76	324	15
14.	उत्तर प्रदेश .	1	0.72	112	25
15.	पश्चिम बंगाल . . .	3	0.90	146	46
जोड़ .		200	91.38	16167	3720